भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

.....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 124*

(03 दिसम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

124*. श्री ईश्वरलाल शंकरलाल जैन :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अत्यंत कम उन्नति हुई है और शहरों की तुलना में गांवों का विकास लगभग नगण्य रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार इस संबंध में विशेष पैकेज निर्धारित कर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किए जाने का विचार रखती है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री जयराम रमेश)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

राज्य सभा में दिनांक 03.12.2012 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 124 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों एवं गांवों और शहरों का विकास देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय से आंका जा सकता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (राष्ट्रीय लेखा प्रभाग) से प्राप्त दो अद्यतन वर्षों की जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्रों के निवल घरेलू उत्पाद (एनडीपी) द्वारा आंकी गई प्रति व्यक्ति आय 1999-2000 में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय से 2.85 गुणा और 2004-05 में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय से 2.69 गुणा अधिक पाई गई। वर्ष 2004-05 के बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आय के अंतर के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अतः, स्पष्ट है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर वर्ष 1999- 2000 से वर्ष 2004-05 के बीच कम हुआ है।

(ग) से (ड.) सरकार इस अंतर को कम करते हुए अंततः समाप्त कर देने के उद्देश्य से सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों और विशेषकर गांवों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाती रही है। पर्याप्त रूप से उपयोगी रोजगार के अवसर पैदा करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी है। गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए सरकार वर्ष 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चला रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण रोजगार के सृजन, ग्रामीण आवास, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, वाटरशेड आधारित क्षेत्र विकास और लक्षित वर्गों के लिए सामाजिक सहायता के क्षेत्रों में प्रमुख योजनाएं चला रहा है, जिनका उद्देश्य ग्रामीण आबादी की आय को बढ़ाकर और उनके जीवन-स्तर में सुधार लाकर ग्रामीण क्षेत्रों और विशेषकर गांवों का विकास करना है। भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने और मौजूदा कार्यक्रमों से पर्याप्त रूप से पूरी न की जा सकी विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों के विकास के विशेष पैकेज भी तैयार किए हैं। इन पैकेजों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) जिलों के लिए विशेष पैकेज, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इत्यादि के बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सूखा उपशमन कार्यनीतियां चलाने के लिए विशेष पैकेज शामिल हैं।